

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2019 — ज्येष्ठ 7, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 28 मई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3.— यतः, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उल्लिखित “नियुक्ति के लिए पात्रता” संबंधी प्रावधान को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 17 जनवरी, 2012 द्वारा उपांतरित करते हुए, आदेशित किया गया था कि “इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे”;

और यतः, उक्त अधिसूचना, 17 जनवरी, 2012 को दो वर्ष की कालावधि के लिए जारी किया गया था, जो 16 जनवरी, 2014 तक प्रवृत्त था;

और यतः, उक्त अधिसूचना की अवधि को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 19 मई, 2014 द्वारा एक वर्ष अर्थात् 17 जनवरी, 2014 से 16 जनवरी, 2015 तक की कालावधि के लिए बढ़ाया गया था और पुनः उक्त अधिसूचना की अवधि को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 10 मार्च, 2015 द्वारा दो वर्ष अर्थात् 17 जनवरी, 2015 से 16 जनवरी, 2017 की अवधि के लिए तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 25 फरवरी, 2017 द्वारा दो वर्ष अर्थात् दिनांक 17 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के लिये बढ़ाया गया था;

और यतः, पुनः यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि को आगामी तीन वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाया जाये तथा इसका विस्तारण कोरबा जिले के निवासियों के लिए भी किया जावे;

अतएव, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, निर्देशित करते हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उक्तवत् वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया उपांतरण, आगामी तीन वर्ष अर्थात् 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2021 की कालावधि के लिए निरंतर प्रवृत्त रहेगा तथा यह कोरबा जिले के निवासियों के लिए भी विस्तारित होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 मई 2019

क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 28-05-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 28th May 2019

NOTIFICATION

No. F1-1/2012/1-3 . — Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-para (1) of para 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, modified the provision regarding “eligibility for appointment” mentioned in rule 5 of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 made by the State Government under Article 309 of the Constitution of India vide Notification No. F 1-1/2012/1-3, Dated 17th January, 2012, ordered that “Notwithstanding anything contained in these rules or any other Act, Order, Direction, Rules of Law for the time being in force, only local residents of the districts falling under Baster and Sarguja Division, shall be eligible for recruitment to the vacancies arising in class III and class IV posts of the district cadre in various departments of the concerned districts, for a period of two years from the date of issue of the said Notification”;

And Whereas, the said notification was issued on 17th January, 2012 for a period of two years and was in force till 16th January, 2014;

And Whereas, the term of the said notification was extended for a period of one year i.e. from 17th January, 2014 to 16th January, 2015 vide Notification No. F 1-1/2012/1-3, Dated 19th May, 2014; and again, the term of the said Notification was extended for a period of two years i.e. from 17th January, 2015 to 16th January, 2017 vide Notification No. F1-1/2012/1-3, Dated 10th March, 2015; and for a period of two years i.e. from 17th January, 2017 to 31st December, 2018 vide Notification No. F1-1/2012/1-3, Dated 25th February, 2017;

And Whereas, again it has become necessary to extend the term of the said Notification for a further period of three years and it shall also extend for the residents of Korba District;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-para (1) of para 5 of the Fifth Schedule of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, directs that modification made by the said Notifications in the rule 5 of the Chhattisgarh Civil Services (General Condition of Services) Rules, 1961 shall remain continuously in force for a further period of three years i.e. from 1st January, 2019 to 31st December, 2021 and shall also extend to the residents of Korba District.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Secretary.